शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-15 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 10-17 अप्रैल 2023 मूल्य पांच रूपए

क्या एटिक फ्लोर को लेकर दी गयी राहत आचार संहिता का उल्लंघन है?

- क्या इस राहत को एन.जी.टी. की अनुमति मिल पायेगी?
- क्या इसका वोटरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा?
- क्या प्रशासन ने नेतृत्व के सामने यह स्थिति नहीं रखी होगी?

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला में चुनाव प्रक्रिया चल रही है और इसके परिणाम स्वरूप निगम क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू है। इस संहिता के चलते नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकते जिसका प्रभाव निगम क्षेत्र के निवासियों पर पड़ता हो। लेकिन सुक्खू सरकार ने 13 अप्रैल को हुई मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसला ले कर सबको चौंका दिया कि सरकार एटिक फ्लोर को वाकायदा रहने लायक बनाने के लिये 2014 के टी.सी.पी. नियमों में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए चार और 15A में संशोधन करके एटिक की ऊंचाई बढ़ाने का प्रावधान किया जायेगा। स्मरणीय है कि मकानों के नक्शे पास करवाने की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों में ही आती है। जहां पर एन.ए.सी. नगरपालिका या नगर निगम है। इसमें भी सबसे ज्यादा समस्या नगर निगम शिमला क्षेत्र की है। जहां पर नौ बार कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रिटैन्शन पॉलिसियां ला चुकी है। कई बार प्रदेश उच्च न्यायालय सरकारों के प्रयासों पर कड़ी टिप्पणियां करते हुये अंकुश लगा चुका है। क्योंकि शिमला भूकंप के मुहाने पर खड़ा है और राज्य सरकार अपनी ही रिपोर्टों में यह स्वीकार भी कर चुकी है।

1971 में किन्नौर में आये भूकंप के दौरान शिमला का लक्कड़ बाजार क्षेत्र और रिज जो प्रभावित हुआ था वह आज तक पूरी तरह संभल नहीं पाया है। शिमला की इस व्यवहारिक स्थिति और सरकार के अपने ही अध्ययनों का संज्ञान लेते हुये एन.जी.टी. ने 2016 में शिमला में अढ़ाई मंजिल से अधिक के निर्माणों पर रोक लगा दी थी और कोर क्षेत्र में तो नये निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया था। शिमला से कार्यालयों को बाहर ले जाने की राय दी है। शिमला में अढाई मंजिल से अधिक के निर्माणों पर इसलिये प्रतिबन्ध लगाया गया है क्योंकि शिमला की और भार सहने की क्षमता नहीं रह गयी है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने पुराने भवन को गिराकर नया बनाने की अनुमति एन.जी.टी. से मांगी थी जो नहीं मिली और उच्च न्यायालय ने इस इन्कार को चुनौती नहीं दी है। सरकार ने एन.जी.टी. के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एन.जी.टी. के फैसले को स्टे नहीं किया है।

जयराम सरकार के समय में शिमला के लिये एन.जी.टी. के आदेशों के अनुसार एक स्थाई प्लान बनाने के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों के तहत यह प्लान तैयार भी हुआ और इसमें भवन निर्माण के लिये कई राहतें दी गयी थी। जैसी अब एटिक फ्लोर के लिये दी गयी है। बड़ी धूमधाम से पत्रकार वार्ता में यह 250 पन्नों का प्लान जारी किया गया। लेकिन अन्त में अदालत ने इसे अपने निर्देशों की उल्लंघना करार देकर निरस्त कर दिया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब एन.जी.टी. के निर्देशों की अवहेलना करके बनाये गये प्लान को रिजैक्ट कर दिया गया है तो अब एटिक की ऊंचाई 2.70 मीटर से 3.05 मीटर करके उसको नियमित करने के फैसले को कैसे अदालत अपनी स्वीकृति दे देगी फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सरकार का फैसला वहां तक पहुंचेगा ही। ऐसे में यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि प्रशासन के सामने यह सारी स्थिति स्पष्ट थी तो क्या प्रशासन ने मंत्रिपरिषद को इससे अवगत नहीं कराया होगा? क्या प्रशासन की राय को नजरअंदाज करके राजनीतिक नेतृत्व ने वोट की राजनीति के लिये यह लुभावना फैसला ले लिया। कानून के जानकारों की राय में यह राहत एन.जी.टी. के फैसले की अवहेलना है और इसका लागू हो पाना संदिग्ध है। जबकि इसके बिना भी सरकार की स्थिति मजबूत थी।

तीन विधानसभा क्षेत्रों में फैले नगर निगम शिमला को एक ही क्षेत्र में क्यों नही लाया जा सकता

निगम चुनावों में उठने लगा है यह सवाल भी

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थानीय निकाय है जो तीन विधानसभा क्षेत्रों शिमला ग्रामीण, कुसुम्पटी और शिमला शहरी में एक साथ फैला हुआ है। शिमला को नगर निगम बनाने और यहां कार्यरत कर्मचारियों को राजधानी भत्ते का पात्र बनाने के लिये इसकी सीमाओं का विस्तार किया गया था। नगर निगम में जो वार्ड शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्रों में शामिल किये गये हैं उनमें आज भी वह सभी सुविधाएं उसी स्तर और अनुपात में उपलब्ध नहीं है जो शिमला शहरी में उपलब्ध हैं। लेकिन भवन निर्माण आदि को लेकर जो नियम शिमला शहरी में लागू है वही इन क्षेत्रों में भी लागू है। कई बार इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन निगम चुनावों में यह विसंगति कभी मुद्दा नहीं बन पायी है। क्योंकि इन वार्डों में से कभी कोई ऐसा नेतृत्व नहीं उभर पाया है जो स्थापित नेतृत्व के लिये चुनौती बन सके। क्योंकि यहां का नेतृत्व विधानसभा चुनाव के समय दो क्षेत्रों में एक साथ बंटकर रह जाता है और कहीं भी प्रभावी राजनीतिक गणना में नहीं आ पाता है। इस वस्तुस्थिति में यह सवाल उभरने लगा है कि जब शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी में पड़ने वाले नगर निगम के वार्ड सारी व्यवहारिकताओं के लिये नगर निगम शिमला का हिस्सा है तो फिर इन वार्डो को स्थाई रूप से शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा क्यों नहीं बना दिया जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से यह सारे वार्ड एक ही प्रशासनिक इकाई का अंग बन जायेंगे। आज नगर निगम चुनाव में यह निगम का हिस्सा है और विधानसभा चुनाव में शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी का हिस्सा होते हैं। लेकिन विकासात्मक कार्यों के लिए दो जगह एक साथ बंटे होने से भी कहीं से भी कुछ भी पाने में पिछड़ जाते हैं। इसलिये यह प्रश्न उठ रहा है कि इन्हें शिमला शहरी विधानसभा का हिस्सा बना दिया जाये।

राज्यपाल ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉ.बी.आर.अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान द्वारा कला केन्द्र, सोलन में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर युग प्रवर्तक एवं भारतीय संविधान के

निर्माता थे। डॉ.अम्बेडकर किसी एक वर्ग से संबंधित नहीं बल्कि समस्त मानवता से जुड़े वैश्विक विभूति थे। उनका समानता का सन्देश आज के दौर में और भी प्रासंगिक है।

राज्यपाल ने कहा कि संविधान निर्माता होने के साथ-साथ डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध कार्य करते हुए गरीबों, शोषितों और दलितों की बेहतरी के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विशेष रूप से सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने भाईचारे के संदेश, विचारों और सिद्धांतों को प्रसारित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संविधान को आत्मसात करने के उपरान्त देश के नागरिकों ने शांति, शिष्टता और प्रगति के पथ पर अग्रसर एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक, स्वशासित आधुनिक भारत में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक अनूठा दस्तावेज है, जिसके लिए हम बाबा साहेब के योगदान को कभी नहीं भुला सकते।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महान विभूति और उनके योगदान को विशेष महत्व दिया और बाबा साहेब से जुड़े तीर्थ स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया ताकि उनकी स्मृतियां अक्षुण रहें और आने वाली पीढ़ियां उनकी तपस्या और बलिदान से सीख ले सकें।

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का समानता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संदेश आज अधिक प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व और कृतत्व विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है और उनकी विरासत को समाज के दलित और वंचित वर्गों के लिए हमेशा आशा की किरण के रूप में याद किया जाएगा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कृष्ण लाल सहगल, कुलराकेश पंत, डॉ. योगराज, ट्विंकल शर्मा और लगन सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया।

सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उनका संदेश संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि वे एक महान अर्थशास्त्री, सामाजिक क्रांति के दूत और शिक्षाविद् थे तथा सभी धर्मों के लोग उन्हें समान रूप से मानते हैं।

डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि डॉ. अंबेडकर का ज्ञान, शोध और अनुभव हमें संविधान के रूप में मिला है। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम एक भारत के सपने को साकार कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने डॉ.भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती

पर अंबेडकर चौक, शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समरसता, सौहार्द और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया। उनके अनुसार समतावादी समाज के निर्माण के लिए शिक्षा प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों और गरीबों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के लिए जीवन-भर कार्य किया। हमें उनके जीवन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी के कैलेंडर का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के कलाकारों ने भक्ति संगीत प्रस्तुत किया।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक विनय कुमार और हरीश जनारथा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, आयुक्त नगर निगम आशीष कोहली और अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने हिमाचल दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों को 76वें हिमाचल दिवस पर बधाई दी है।

अपने शुभकामना सन्देश में राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कुदरत ने इसे अपार प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से नवाजा है। उन्होंने कहा कि यहां के मेहनती एवं कर्मठ लोगों ने राज्य के विकास में अपना भरपूर योगदान दिया है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी प्रदेशवासियों के रचनात्मक सहयोग से हिमाचल प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। उन्होंने राज्य के लोगों की सफलता और खुशहाली की भी कामना की।

किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक करें वैज्ञानिक: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के निकट क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र मशोबरा का दौरा किया। केंद्र के अपने पहले दौरे पर राज्यपाल ने वैज्ञानिकों का आहवान किया कि वे संस्थानों से

बाहर निकलकर अपने क्षेत्र में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि किसान इसके लाभ जानकर निश्चित रूप से इस पद्धति को अपनाएगे।

उन्होंने इस केंद्र में प्राकृतिक खेती मॉडल के रूप में विकसित किए गए प्रदर्शन बागों के अवलोकन में गहरी रुचि दिखाई और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार इस कृषि पद्धति के परिणामों से प्रभावित हुए। उन्होंने बागवानी विश्वविद्यालय से जुड़े वैज्ञानिकों और सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि परियोजना के अधिकारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई भी दी।

राज्यपाल ने औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा केन्द्र में आयोजित 'प्राकृतिक खेती-सुरक्षित विकल्प' विषय पर किसानों और वैज्ञानिकों के संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसान आज न केवल अपनी आय बढ़ा रहे हैं बल्कि सकल उत्पादन बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य की सेब आधारित अर्थव्यवस्था लगभग 5000 करोड़ रुपये की है। हमारे किसान और फल उत्पादक प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के अतिरिक्त अब फल उत्पादनक में भी हिमाचल की एक विशिष्ट पहचान है। आज किन्नौर का सेब विदेशों में ऊंचे दामों पर बिक रहा है, जिससे हिमाचल का महत्व और भी बढ़ गया है।

किसानों के सुझावों और जानकारी से प्रभावित राज्यपाल ने उनके के बागीचों में जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व बैंक प्राकृतिक खेती करने वाले फल उत्पादकों की मदद के लिए आगे आ रहा है और जापान और अन्य देशों के लोग भी उनके खेतों का दौरा कर रहे हैं। आज बड़े उत्पादक स्वरोजगार को और प्रोत्साहन करने की स्थिति में हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हिमाचल प्राकृतिक खेती में एक आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा।

राज्यपाल ने कहा कि इस केंद्र ने बागवानी विकास और समशीतोष्ण फल उद्योग की व्यवहारिक समस्याओं और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह केंद्र विशेष रूप से सेब उत्पादन एवं संबद्ध उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्राकृतिक खेती के संबंध में कई बार हिमाचल का उल्लेख और प्रशंसा कर चुके हैं और अब उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर राज्यपाल एवं लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने केन्द्र परिसर में पौधरोपण भी किया।

इससे पहले, डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसानों और वैज्ञानिकों के समन्वय से प्राकृतिक खेती की विशेष कृषि प्रणाली विकसित की गयी है। किसानों को केंद्र में रखकर प्राकृतिक खेती पद्धति को लागू किया गया है। किसान और फल उत्पादक स्वेच्छा से इसे अपना रहे हैं और इसकी सफलता उन्हीं पर निर्भर करती है।

सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के परियोजना निदेशक, नरेश ठाकुर ने कहा कि परियोजना मॉडल के तहत प्रत्येक पंचायत में प्राकृतिक खेती के फार्म विकसित किए जाएंगे और इस वर्ष 100 ऐसे गांवों का चयन किया जाएगा, जहां हर किसान प्राकृतिक खेती अपनायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने नि:क्षय मित्र और टी.बी. चैंपियन को पुरस्कृत किया

शिमला/शैल। ऊना जिला प्रशासन के साथ टीबी उन्मूलन पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नि:क्षय मित्र की प्रेरणा सभी को मिलनी चाहिए, तभी लोग स्वेच्छा से आगे आएंगे।

राज्यपाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया में टी.बी. उन्मूलन की दिशा में गंभीरता से काम हो रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्वयं लोगों को इस बारे में प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अधिकांश लोग टीबी उन्मूलन के प्रति जागरूक हैं लेकिन उनका सक्रिय योगदान लेने की आवश्यकता है। इसके लिए विभाग के कर्मियों को क्षेत्र में निकलने की जरूरत है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नि:क्षय मित्र बनने में राजभवन भी हरसंभव मदद देगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टी.बी. रोगियों को दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए और समय-समय पर रोगियों से बात कर उनकी प्रतिक्रिया भी लेते रहें।

राज्यपाल ने इस अवसर पर रेडक्रॉस की वार्षिक रिपोर्ट जारी की तथा रेडक्रॉस के रैफरल ड्रॉ के 5 विजेताओं को 1.12 लाख रुपये हजार रुपये का चेक भेंट किया। उन्होंने नि:क्षय मित्र और टी.बी. चैंपियन को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने टी.बी. चैंपियन और नि:क्षय मित्र से संवाद भी किया।

राज्यपाल ने टी.बी. रोगियों को हाईजीन किट और न्यूट्रिशन किट भी वितरित किए।

उपायुक्त ने राज्यपाल जिला स्तर पर टी.बी. उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मंजु बहल ने टी.बी. उन्मूलन में विभागीय गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत करवाया।

डब्ल्यू.एच.ओ. परामर्शी डॉ. आत्मिका नायर ने टी.बी. कार्यक्रम के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। रोहित जाफा के दिवांश और गोल्डी द्वारा डिजीटल हैंड एक्स-रे मशीन की प्रस्तुति भी दी गयी।

बद्दी में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सोलन जिले के बद्दी में इस वर्ष पहली अक्तूबर से उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) का कार्यालय खोला जाएगा। यह घोषणा

मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र के पहले दौरे के दौरान हनुमान चौक बद्दी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए की। उन्होंने बद्दी में बीएमओ कार्यालय और झारमाजरी में पटवार वृत खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने अधिकारियों को बद्दी बस स्टैंड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर 92,840 रुपये का ऋण है, जिससे राज्य को आर्थिक संकट के दौर का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि राज्य के विभिन्न व्ययों का प्रबंधन करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार को पिछली सरकार की देनदारियों को चुकाने के लिए 6000 करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद वे वित्तीय अनुशासन के दृष्टिगत निर्णय लेकर राज्य की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार संसाधन जुटाने के लिए काम कर रही है, ताकि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य के पास धन उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई निवेश नीति लायी जा रही है, जिससे उद्यमियों के साथ-साथ प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा निवारण व मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत भी गंभीर प्रयास कर रही है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस संबंध में सख्त कानून बनाने का आग्रह भी किया है।

इस अवसर पर शिवालिक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी झारमाजरी ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर को एक लाख रुपये का चेक भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र में 22.30 करोड़ रुपये की लागत की पांच विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र के बुघार में बनिया देवी-बुघार मार्ग पर गंभर खड्ड पर 5.16 करोड़ की लागत के पुल का लोकार्पण किया जिससे कि अर्की, दून और कसौली विधानसभा क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने बद्दी क्षेत्र के कल्याणपुर में 3.33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित महिला पुलिस थाने का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने हरिपुर से चुनरी संपर्क रोड में सिरसा खड्ड पर 11.44 करोड़ रुपये की लागत के 180 मीटर लंबे डबल लेन पुल का शिलान्यास, बद्दी में सनसिटी रोड पर 1. 50 करोड़ रुपये की लागत से साइकिल ट्रैक और 87 लाख रुपये की लागत से बनने वाले लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय एवं आवासीय भवन का शिलान्यास भी किया।

मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने बद्दी में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार दून विधानसभा क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए हमेशा संवेदनशील रही है। उन्होंने बद्दी में एसडीएम कार्यालय और बीएमओ कार्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, सुरेश कुमार और के.एल. ठाकुर, कांग्रेस के नेतागण और वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल गौरव और प्रेरणास्रोत पुरस्कार प्रदान किए

शिमला/शैल। हिमाचल दिवस के अवसर पर लाहौल स्पीति के काजा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाज सेवा, खेल, संस्कृति के संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न व्यक्तित्वों को 'हिमाचल गौरव' और 'प्रेरणास्रोत' पुरस्कार से सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं के छत्त प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक लकेश चंदेल को 'हिमाचल गौरव' पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने स्कूल भवन के समीप भू-स्खलन में 36 विद्यार्थियों की जान बचाई थी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोकगीतों को संरक्षित करने के लिए प्रदेश के प्रसिद्ध गायक करनैल राणा और साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सोलन जिले के नेम चंद को 'हिमाचल गौरव' पुरस्कार से सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिले की रानी को खेल गतिविधियों में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रदान किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश की टीबी उन्मूलन टीम को 'सिविल सेवा पुरस्कार' प्रदान किया गया।

पाइनग्रोव स्कूल कसौली के कार्यकारी निदेशक कैप्टन अमर्योत सिंह, मंडी जिले के पदमश्री नेक राम शर्मा और शिमला जिला के कोटखाई के प्रेम सिंह चौहान को प्रेरणास्रोत अवार्ड से सम्मानित किया गया।

कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री के संकल्प को नया बूस्ट देगा जी20 शिखर सम्मेलन

शिमला/शैल। इसी हफ्ते धर्मशाला में होने जा रहे जी 20 शिखर सम्मेलन से हिमाचल को दुनिया भर में ब्रांडिंग करने का एक बेहतर अवसर मिला है। यह सम्मेलन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के संकल्प को और आगे बढ़ाने में मददगार होगा। लिहाजा, प्रदेश की सुख की सरकार इसे हर तरह से यादगार बनाने में जुटी है।

19-20 अप्रैल को होने वाले इस सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा के लिए विभिन्न देशों के 70 प्रतिनिधि धर्मशाला आयेंगे। हिमाचल में उनके प्रवास को यादगार बनाने के लिए तमाम प्रबंध किये गये हैं। साथ ही उन्हें हिमाचल और कांगड़ा की ऐतिहासिक धरोहर, विरासत, संस्कृति, खानपान, कला, हैंडीक्राफ्ट से भी रूबरू करवाया जाएगा, ताकि वे यहां की समृद्ध संस्कृति की नई तस्वीर अपने संग सहेज कर साथ ले जायें। भविष्य में इसका सीधा लाभ हिमाचल के पर्यटन उद्योग को भी मिलेगा।

हिमाचल को जी 20 की मेजबानी मिलना प्रदेश की सुख की सरकार पर केंद्र के भरोसे और मुख्यमंत्री की धारदार कार्यशैली और कार्यकुशलता का परिणाम है। अपार प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता की दृष्टि से जी 20 बैठक के आयोजन के लिए धर्मशाला बेहतर शहर है।

जी 20 सम्मेलन में 'रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग' विषय के तहत नवीनतम अनुसंधान और नवाचारों पर चर्चा होगी। जी 20 सम्मेलन के आयोजन के लिए होटल रेडिसन ब्लू को चिन्हित किया गया है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे विभिन्न देशों के साइंटिस्ट, नीति-निर्माता और विशेषज्ञों का 18 अप्रैल को कांगड़ा हवाई अड्डे पर हिमाचली परंपरा के अनुरूप स्वागत-सत्कार किया जाएगा। साथ ही उन्हें सिद्दू तथा अन्य हिमाचली पकवान और एप्पल टी, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा टी जैसे पेय का जायका उपलब्ध करवाया जाएगा।

19 अप्रैल को दिन में तकनीकी सत्र होंगे, रात्रि में मेहमानों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एचपीसीए में 'गाला डिनर' का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मेहमानों को हिमाचली टोपी-शॉल के अलावा कांगड़ा पेंटिंग्स देकर सम्मानित करेंगे। इस दौरान प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाने के लिए विविध सांस्कृतिक नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम का आयोजन भी रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, सिरमौर, किन्नौर और चंबा जिले की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।

20 अप्रैल को आयुष विभाग के सौजन्य से योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके उपरांत प्रतिनिधि धर्मशाला व आसपास के स्थानों का भ्रमण करेंगे। धर्मशाला के नरघोटा में चाय बागानों का दीदार करने के साथ ही बागान में चाय की पत्तियां चुनने का अनुभव भी लेंगे। मान टी फैक्टरी में चाय की प्रोसेसिंग जानने के साथ ही चाय के विविध फ्लेवर्स का टेस्ट भी लेंगे। उसके उपरांत वे कांगड़ा कला संग्रहालय में हिमाचली कला-संस्कृति और शिल्प से रूबरू होने के साथ ही लाईव कांगड़ा पेंटिंग का भी अनुभव ले सकेंगे।

सम्मेलन स्थल पर आईएचबीटी पालमपुर और कृषि विश्वविद्यालय द्वारा साइंस-प्रौद्योगिकी के नवाचार से जुड़ी प्रदर्शनी लगायी जाएगी और हथकरघा-हस्तकला से जुड़े उत्पादों के प्रदर्शनी व बिक्री काउंटर भी लगाये जाएंगे। डेलीगेट्स यदि चाहें तो उन उत्पादों को खरीद भी सकेंगे। इसके लिए यूपीआई आधारित भुगतान की व्यवस्था रहेगी।

जी 20 में अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया,रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाईटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने को संकल्पबद्ध हैं। ऐसे में जी 20 समूह के प्रतिनिधियों को यहां आगमन बहुत उत्साहवर्धक है। यह दुनिया भर में प्रदेश की ब्रांडिंग का शानदार मौका है। सरकार का प्रयास है कि सम्मेलन में आने वाले मेहमान यहां से प्रदेश की एक अच्छी छवि लेकर जायें।

स्कूल लेक्चरर के 530 पद भरने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के लेक्चरर (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने आम जनता की सुविधा के लिए एटिक "लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने निर्धारित वेतन (एमोल्यूमेन्टस) पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के अन्तर्गत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सरकार द्वारा अनुबंध सेवा की अवधि एवं वेतन (एमोल्यूमेन्टस) को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (एचपीएएस) के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक के दो पदों को नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम, 1989 के नियम 50 में संशोधन करने का निर्णय लिया। राजस्व बढ़ाने की दिशा में उठाये गये इस कदम से अब वार्षिक लाइसेंस शुल्क डेढ़ लाख रुपये होगा।

मंत्रिमण्डल के समक्ष राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर प्रस्तुति भी दी गयी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह

शिमला/शैल। लोक निर्माण तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट की।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश ने केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-3 के तहत 2813 करोड़ रुपए की लागत की 2565 किलोमीटर लम्बी 242 सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रेषित की है। उन्होंने इन सड़कों के निर्माण कार्यों की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-3 के तहत 3125 किलोमीटर सड़क निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें बैच एक के तहत गत वित्तीय वर्ष के दौरान 440 किलोमीटर सड़कों के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-3 के माध्यम से राज्य में ग्रामीण सड़क सुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार से उदार सहायता एवं सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना तथा हरसम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बड़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

नई शिक्षा नीति पर उठे सवाल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गयी है। इसे लागू करने के साथ ही कक्षा बारहवीं तक के पाठयक्रमों में एन.सी. आर.टी. ने बदलाव किया है। पाठयक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी एन.सी.आर.टी. की है। पिछले दिनों जब देश कोविड से जूझ रहा था और लॉकडाउन लगाना पड़ा था तब सबसे ज्यादा स्कूल पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित हुये थे। ऑनलाइन क्लासें लगाई गयी थी। इसका संज्ञान लेते हुये एन.सी.आर.टी. ने 30 प्रतिशत तक पाठयक्रमों में कटौती करने का फैसला लिया। स्वभाविक है कि जब पाठयक्रम घटाया जायेगा तो निश्चित रूप से किताबों से कुछ अध्याय हटाने पड़ेंगे। इससे जिस तरह से अध्याय हटाये गये हैं उससे हटाने वालों की नीयत पर संकाएं उठना शुरू हो गयी है। क्योंकि कोविड के कारण 30 प्रतिशत पाठयक्रम बच्चों का बोझ कम करने के नाम पर घटाया गया लेकिन जब कोविड की आशंका नहीं रहेगी तब फिर से हटाये गये अध्यायों को पाठयक्रम का हिस्सा बना दिया जायेगा यी नहीं कहा जा रहा है। यही सरकार की नीयत पर संदेह का आधार बन रहा है। क्योंकि जो अध्याय हटाये गये हैं उनके बिना शिक्षण और ज्ञान दोनों अधूरे रह जाते हैं।

इस देश में अंग्रेजों से बहुत पहले मुस्लिम आ गये थे। उनका शासन भी देश में रहा है। वह देश में बस गये और यही का हिस्सा बन गये। अंग्रेजो के खिलाफ आजादी की लड़ाई में उनका भी योगदान रहा है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई जिसे झूठलाया नहीं जा सकता। जो निश्चित रूप से सच हो उसे ही इतिहास कहा जाता है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान दूसरों से अधिक रहा है। गांधी उसके नायक रहे हैं। मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन इस लड़ाई में देश के हवाले कर दिया था। क्या इन तथ्यों को झूठलाया जा सकता है शायद नहीं। स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की आजादी की लड़ाई में रही भूमिका पर जो सवाल भाजपा नेता डा. स्वामी ने उठाये हैं क्या उनका जवाब किसी ने आज तक दिया है? गांधी, नेहरू और मुगल इतिहास के अध्यायों को पाठयक्रम से हटाकर इतिहास से नहीं मिटाया जा सकता। ईसा को किसी पाठय पुस्तक में अपशब्द कहकर उनकी महानता को कम नहीं किया जा सकता। पाठयक्रमों में मनुस्मृति और श्री मदभगवत् गीता को जोड़कर इतिहास को नये सिरे से नहीं लिखा जा सकता। जो प्रयास संघ के इतिहास लेखन प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जा रहा है।

पाठयक्रमों से अध्यायों को हटाने जोड़ने से ज्यादा संवेदनशील मुद्दा यह है कि अब बच्चों को पाठयक्रमों में विस्तृत चुनाव पर विकल्प दे दिये गये हैं। अब पाठयक्रम ''अतिरिक्त पाठयक्रम'' या सह पाठयक्रम कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यवसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणीयां नहीं होगी। यह विषय बच्चों की रूची के अनुसार पाठयक्रम में शामिल किये जायेंगे। पहले प्लस टू के बाद बच्चा एक धारा विशेष में जाने का पात्र हो जाता था। क्योंकि सारी व्यवसायिक शिक्षा प्लस टू के बाद पंचवर्षीय हो चुकी है। अब क्योंकि कोई धारा ही नहीं होगी तो वह अगला विकल्प क्या और कैसे चुनेगा। दो वर्ष बाद जो बच्चे प्लस टू करके निकलेंगे उनके लिये यह व्यवहारिक कठिनाई खड़ी होगी। इस समय जो बहस पाठयक्रमों में कटौती करके हटाये गये अध्यायो पर केंद्रित होकर रह गई है उसमें प्लस टू के बाद आने वाली स्थिति पर विचार करना आवश्यक है।

मस्जिदों के निर्माण में महिलाओं की भूमिका है तो फिर नमाज पढ़ने में क्या परेशानी?

गौतम चौधरी

वर्तमान प्रगतिशील दौर में यदि मुस्लिम महिलाओं को सशक्त किया जाये तो वह मस्जिद व खानकाहों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर व्यापक मुहिम चला सकती है। यहां एक बात बता दूं कि पुराने समय में भी राजनीतिक रूप से, मुस्लिम महिलाओं को सम्राटों द्वारा विश्वास में लिया गया था। दुनिया के प्रभावशाली इस्लामिक सम्राटों ने उन महिलाओं से हर स्तर पर उनसे सलाह ली और उसे सत्ता एवं शासन में क्रियान्वित किया। इतिहासकारों की मानें तो मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर ने भी लड़ाई के लिए बाहर निकलने से पहले अपनी महिलाओं, माँ, पत्नियों और बेटियों से सलाह ली थी। भारतीय मध्यकालीन युग में मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत रजिया सुल्तान और महम अंगा के उदाहरणों से की जा सकती है।

दिल्ली सल्तनत की शासक रजिया सुल्तान 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली की पहली महिला शासक बनीं। रजिया सौतेले भाई मुइज उद-दीन बहराम से पहले गद्दी पर बैठी। वह प्रशासन में निपुण थी और युद्ध में सल्तनत का नेतृत्व करने में सक्षम थी। लेकिन उस समय उलेमाओं ने शुरू में उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था। सल्तनत का नियंत्रण संभालने के लिए, वह मेहरौल्ट में कुव्वतुई इस्लाम मस्जिद गई, जिसे उत्तर भारत की पहली मस्जिद कहा जाता है। उन्होंने शुक्रवार के दिन ऐसा किया, जब मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी उपस्थित थे। रजिया ने अपनी सल्तनत की सुरक्षा के लिए मस्जिद में उपस्थित प्रभावशाली लोगों के सामने अपना दावा पेश किया। कुव्वतुई इस्लाम मस्जिद में अपने संबोधन से, रजिया ने न केवल अन्य महिलाओं को मस्जिद जाने के लिए तर्क प्रस्तुत किए बल्कि मस्जिद बनाने के लिए भी रास्ता दिखाया। उस दिन खुतबा भी उनके नाम पर पढ़ा गया, जो भारत की तारीख में दर्ज इतिहास ऐसा पहला खुतवा है।

दिल्ली में खैरुल मंजिल मस्जिद जिसे 1561 में महानतम मुगल शासक जलालुद्दीन अकबर की पालक मां महम अंगा ने बनवाया था। कहा जाता है कि यह दिल्ली की पहली मस्जिद है जिसे किसी महिला ने तामीर की थी। मस्जिद के केंद्रीय मेहराब में एक शिलालेख है, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि मस्जिद का निर्माण महम अंगा द्वारा किया गया था। संयोग से, कई मुगल राजकुमारियों ने भी मस्जिदों का निर्माण करवाया था। मस्जिद से जुड़ा एक मदरसा था, जो बच्चों की इस्लामी शिक्षा के लिए खुद अंगा द्वारा वित्त पोषित था।

मध्ययुगीन भारत में कई मस्जिद शाही महिलाओं और यहां तक कि रईसों के परिवारों द्वारा पोषित थे। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, सूफी खानकाहों और दरगाहों में भी महिलाएं जाती थीं और कहा जाता है कि उन्होंने सूफियाना कलाम गाने में बड़े उत्साह के साथ भाग लेती थी। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर 13वीं शताब्दी की शुरुआत से, महिलाएं खानकाहों के संरक्षण में लगातार अपना योगदान दे रही थीं। चूंकि अधिकांश दरगाहों और खानकाहों से मस्जिदें जुड़ी हुआ थीं, सूफियों ने वहां महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ कोई कठोर वक्तव्य नहीं दिया। यह दिखाने के लिए एक भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है कि महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश करने से कभी मना किया गया हो। उलेमाओं द्वारा मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ फतवा जारी करने का कोई ऐसा पुराना रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के वजीराबाद में एक तुगलक युग की मस्जिद में एक ऊंचा कक्ष है, जो जाली की दीवारों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यहां शाही महिलाओं के नमाज पढ़ने की व्यवस्था थी।

अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि वजीराबाद मस्जिद में जालीदार दीवारों के पीछे का स्थान महिला उपासकों के लिए आरक्षित था। इस मस्जिद में पुरूष श्रद्धालू मुख्य हॉल में नमाज पढ़ते थे और महिलाएं जाली की दीवारों के पीछे नमाज अता करती थी।

मस्जिदों के अंदर महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाले कोई स्पष्ट चिह्न पूरे इस्लामिक इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। मुगलों के पतन और अंग्रेजों के आने के साथ यह सब बदलना शुरू हुआ। फिरंगियों ने अपने तारीके से इस्लाम की व्याख्या करवाई और फालतू के रूढ़ि को इस्लामिक मूल्य कहकर प्रचारित किया। मस्जिद, खानकाह और कब्रिस्तानों से महिलाओं को बेदखल कर दिया गया। आध्यात्मिक उत्थान के लिए उन्हें मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कब्रिस्तान में अपने निकट और प्रिय लोगों की कब्र पर फातिहा करने से भी रोका जाने लगा। इस दौरान महिलाओं का हज के लिए जाना जारी रहा। मध्ययुगीन और आधुनिक काल में भी, महिलाओं को हज पर जाने के अधिकार से कभी वंचित नहीं किया गया था। अन्य इस्लामिक देशों की तरह हमारे देश की महिलाएं भी हज करती रही। मक्का और मदीना दोनों में प्रार्थनाएं करती रही लेकिन अपने यहां उन्हें मस्जिद से वंचित कर दिया गया। आज भी भारत की मुस्लिम महिलाएं पैगंबर मोहम्मद की पत्नियों के अंतिम विश्राम स्थल पर जा रही हैं।

यह कितनी बड़ी विडंबना है कि इस्लाम के भारतीय रूप का मतलब है, महिलाएं मस्जिदों का निर्माण कर सकती हैं, या उनके वित्तपोषण में भाग ले सकती हैं लेकिन उनके अंदर नियमित नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। आज महिलाएं उन मस्जिदों में नमाज के लिए नहीं जा सकती जिन्हें उस युग की प्रभावशाली महिलाओं ने बनाया था। कुल मिलाकर यह अंग्रेजों का खड़ा किया गया फसाद है। अब इसे ठीक किया जाना चाहिए और मस्जिदों में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे न तो इस्लामी मूल्यों को ठेस पहुंचेगा और न ही महिलाओं के अधिकारों का हनन होगा।

सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है

शिमला। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू जैव ईंधन उत्पादन की जरूरत पर बल दिया और कहा कि यह जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अंततः ये नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। वह नई दिल्ली में कप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आईएफजीई) द्वारा किया गया था।

वैकल्पिक ईंधन की जरूरत पर बल देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'जीवाश्म ईंधनों की सीमित घरेलू उपलब्धता और इसमें हमारी आयात निर्भरता को देखते हुए जब तक जीवाश्म ईंधन के विकल्प/अनुपूरक का काम करने वाले वैकल्पिक ईंधनों को स्वदेशी स्थायी नवीकरणीय फीडस्टॉक के आधार पर विकसित नहीं किया जाता है तब तक इस देश की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर बनी रहेगी।'

मंत्री ने कहा कि सीबीजी के उत्पादन के कई फायदे होंगे। जैसे कि प्राकृतिक गैस के आयात में कमी, जीएचजी उत्सर्जन में कमी, कृषि कचरे को जलाने में कमी, किसानों को लाभकारी आय मिलना, रोजगार सृजन, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन आदि। उन्होंने कहा, 'भारत सरकार ने ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 2030 में 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है ताकि भारत को एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। वर्तमान में हम प्राकृतिक गैस की अपनी जरूरत का लगभग 50 प्रतिशत आयात कर रहे हैं। सीबीजी के तेजी से विस्तार से घरेलू संसाधनों से हमारी अतिरिक्त जरूरत पूरा करने में मदद मिलेगी।'

सरकार की नीतियों ने पिछले 10 वर्षों में हरित नवीकरणीय ऊर्जा के अडॉप्शन को सक्षम बनाया है। हरदीप सिंह पुरी ने खास तौर पर 'किफायती परिवहन की दिशा में टिकाऊ सतत विकल्प' (सतत) योजना और कप्रेस्ड बायोगैस पैदा करने के लिए कृषि-कचरे के उपयोग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'सतत पहल के तहत जानवरों के गोबर, कृषि कचरे, एमएसडब्ल्यू (नगर के ठोस कचरे), सीवेज के पानी और औद्योगिक कचरे जैसे प्रेस मड, चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि से निकलने वाली धुलाई जैसे विभिन्न कचरे को बायोगैस/सीबीजी के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में लेने पर काम किया जा रहा है।'

मंत्री पुरी ने 2024-25 तक 5,000 कमर्शियल प्लांट स्थापित करने और 15 एमएमटी सीबीजी का उत्पादन करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी साझा किया, ये सीबीजी देश में इस्तेमाल किए जा रहे अन्य गैस ईंधनों की जगह लेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत ने सतत योजना के तहत 46 कप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र चालू किए हैं और वर्तमान में देश भर में 100 आउटलेट हैं जो कप्रेस्ड बायोगैस का वितरण कर रहे हैं।

इस इकोसिस्टम के बारे में बात करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार 'ट्रिपल बॉटम लाइन' (पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था) के सभी कारकों के लिए स्थिरता को प्रोत्साहित करने हेतु एक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करने में लगातार लगी हुई है। यह दिखलाता है कि सरकार ने किस तरह नीतियां तैयार की हैं, केंद्रीय वित्तीय सहायता के जरिए समर्थन देने वाली योजनाएं बनाई हैं ताकि हरित ऊर्जा के हर प्रकार को अपनाने में समर्थन दिया जा सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकार नियमों को और सरल बनाने के लिए अन्य विभागों और मंत्रालयों के साथ काम कर रही है, जिसके नतीजतन इन परियोजनाओं को अपनाने और लागू करने में आसानी होगी। उन्होंने उर्वरक विभाग का जिक्र किया, जिसने एक 'बास्केट अप्रोच' के तौर पर रासायनिक उर्वरकों के साथ एफओएम के भी अनिवार्य उठाव के लिए उर्वरक कंपनियों को पत्र जारी किया और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केस-टू-केस आधार पर संयंत्रों को 'वाइट कैटेगरी' के दर्जे में शामिल किया।

हरित और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को बताते हुए मंत्री ने ऐसे नवीकरणीय, टिकाऊ और स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों को पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया जो अल्पावधि में दूसरे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के पूरक बन सकते हैं और लंबी अवधि में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे सीबीजी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के एक उप-उत्पाद, किण्वित जैविक खाद (एफओएम) को कृषि क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए लागू किया जा सकता है।

इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के बारे में बात करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि अमृत काल बजट 2023 भारत की बायो-गैस और स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को भारी बढ़ावा देता है:

सीबीजी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने और गोबरधन योजना के तहत 200 सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना की घोषणा के साथ,

नेचुरल और बायो गैस की मार्केटिंग करने वाले सभी संगठनों के लिए पांच प्रतिशत सीबीजी का प्रावधान लाया जाएगा।

ब्लेंडेड कप्रेस्ड नेचुरल गैस पर टैक्स गिरावट से बचने के लिए, ब्लेंडेड सीएनजी में शामिल कप्रेस्ड बायोगैस पर चुकाई गई जीएसटी राशि पर एक्साइज ड्यूटी से छूट दी गई है।

सरकार के समावेशी विकास दृष्टिकोण पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि कृषि और किसान इसका अभिन्न अंग हैं। ग्रामीण भारत में व्यापक तौर पर पाए जाने वाले कृषि और पशु कचरे के उपयोग के जरिए हरित ऊर्जा, विशेष रूप से कप्रेस्ड बायोगैस की ज्यादा से ज्यादा पैठ के माध्यम से वे सीधे लाभान्वित होंगे। उन्होंने विभिन्न राज्यों और हरित ऊर्जा व खासकर कप्रेस्ड बायोगैस को अपनाने को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की सराहना की और कप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने के लिए उन्हें बधाई दी, जो कि लंबी अवधि में देश की एनर्जी बास्केट को बढ़ावा देने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन में अधिक मात्रा में कमी लाये जाने की आवश्यकता

शिमला। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आईपीसीसी एआर 6 रिपोर्ट इस बात पर फिर से जोर देती है कि विकास जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारा पहला बचाव है। यह रिपोर्ट इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की फिर से पुष्टि करती है कि कार्बन डायऑक्साइड प्राथमिक जीएचजी है जिसे वैश्विक तापमान लक्ष्य अर्जित करने के

लिए बेशुमार मात्रा में कम किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि पेरिस समझौते में सहमति हुई थी। जापान के सैप्पारो में जलवायु, ऊर्जा एवं पर्यावरण पर जी7 मंत्रियों की बैठक पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने के वैश्विक लक्ष्य के लिए विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन में अधिक मात्रा में कमी लाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह भारत जैसे देशों को अपने लोगों के लिए आवश्यक विकास अर्जित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा जो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणगत गिरावट और प्रदूषण के प्रभावों के विरुद्ध आवश्यक बचाव प्रदान करेगा।

यादव ने कहा कि औद्योगिक क्रांति के उद्भव के बाद से, आर्थिक वृद्धि और विकास अर्जित करने के लिए जीएचजी का विपरीत अनुपात में बेशुमार उत्सर्जन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण का भी व्यापक रूप से क्षरण हुआ है। यादव ने बताया कि यह प्रकृति के संतुलन में परिवर्तन की कीमत पर हुआ है जिससे पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैवविविधता के नुकसान की चुनौतियों से हमारे ग्रह को बचाने के लिए हमें रियो संधियों के संस्थापक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित सामूहिक कारवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमने यूएनएफसीसीसी, सीबीडी, यूएनसीसीडी की प्रक्रिया के माध्यम से सामूहिक रूप से कुछ प्रगति की है। बहरहाल, जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता के नुकसान और प्रदूषण की तीन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकासशील देशों को भी कार्यान्वयन, वित्त एवं प्रौद्योगिकी के साधनों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम यह उम्मीद जरुर करते हैं कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी करेंगे और पर्यावरण के क्षरण और जैवविविधता के नुकसान से निपटने के लिए इसे उपलब्ध कराएंगे।

यादव ने कहा कि कार्बन तटस्थता और बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा के लक्ष्यों तक पहुंचना तब तक संभव नहीं होगा जब तक उनका निर्माण निष्पक्षता और सीबीडीआर-आरसी विचारों को ध्यान में रख कर नहीं किया जाता तथा जब तक विकसित देश कार्यान्वयन के साधनों को उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरी नहीं करते।

यादव ने कहा कि अभी तक हमारी कारवाइयां जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एक नीतिगत संरचना का सृजन करने पर केंद्रित रही है। यही उपयुक्त समय है जब विश्व भर की सरकारें व्यक्तियों के स्तर पर इसे एक भागीदारी प्रक्रिया बनाने पर ध्यान केंद्रित करें।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत कारवाइयों में क्रांति की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि शर्म अल शेख में सीओपी 27 में, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए टिकाऊ जीवनशैलियों और उपभोग तथा उत्पादन के स्थिर तरीकों के महत्व को रेखांकित किया गया।

यादव ने सभी संबंधित देशों से मिशन लाईफ की भावना में व्यक्तिगत व्यवहार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा, पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाईफ) की तरफ बदलाव लाने के द्वारा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणगत क्षरण और प्रदूषण के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई में विश्व के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया।

अनुराग ठाकुर ने एनसीओई हमीरपुर में बैडमिंटन कोर्ट मैट, जूडो हॉल और बॉक्सिंग हॉल का उद्घाटन किया

शिमला। युवा कार्यक्रम और खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण

राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) में खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण एनसीओई हमीरपुर में बॉक्सिंग हॉल और जूडो हॉल में फर्श के साथ बैडमिंटन कोर्ट मैट स्थापित और संचालित हैं।

मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हमीरपुर की स्थापना की गयी है। वर्तमान में प्रथम वर्ष के लिए गैर-आवासीय आधार पर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, जूडो, हॉकी, कुश्ती के 6 क्षेत्रों में 91 एथलीट प्रशिक्षण ले रहे हैं। एनसीओई के भविष्य के विस्तार का कार्य प्रगति पर है जिसमें प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए विस्तारित 300 बिस्तरों वाले छात्रावास सुविधाओं से सुसज्जित एक अंतरराष्ट्रीय खेल क्षेत्र और ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल तैयार किया जा रहा है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कम समय में कोर्ट के निर्माण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की। ठाकुर ने कहा, 'इस भारतीय खेल प्राधिकरण एनसीओई को पूरा करने में सिर्फ 10 महीने लगे और मैं डॉ. अंबेडकर जयंती पर खुश हूं, हम नए बैडमिंटन कोर्ट, नई प्रकाश व्यवस्था, कुश्ती और जूडो मैट और बहुत कुछ खोल रहे हैं। यह रिकॉर्ड समय में किया गया। इस एनसीओई के लिए और भी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। हम सभी अपने जीवन में डॉ. अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।

ठाकुर ने कहा, 'एनसीओई में यहां बहुत सारे प्रतिभाशाली एथलीट होंगे और इन एथलीटों को यहां जो प्रशिक्षण मिलेगा, वह कौशल और विकास के मामले में उनके करियर को आगे बढ़ाएगा। इससे काफी प्रोत्साहन मिला है और हिमाचल प्रदेश में खेलों के विकास को और बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र को भारत में अगला बड़ा खेल केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य है।'

76वें हिमाचल दिवस के अवसर पर

व्यवस्था परिवर्तन के लिए कटिबद्ध–सुख की सरकार

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

76वें हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश को आज़ादी मिलने के 8 माह बाद 15 अप्रैल 1948 को यह सुन्दर पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी–बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ केन्द्रशासित चीफ कमिशनर्ज़ प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया था।

प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय तत्कालीन नेतृत्व के साथ–साथ प्रजामण्डल आन्दोलन के नायकों व आंदोलनकारियों और यहां की जागरूक जनता को जाता है। हिमाचल प्रदेश के गौरवमयी इतिहास में धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह, पझौता आन्दोलन का विशेष स्थान है।

इस पावन अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता तथा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार तथा उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश को विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अथक प्रयास किए।

हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर मैं प्रदेश के उन सभी बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं कर्मठ व ईमानदार प्रदेशवासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रदेश को देश–विदेश में खास पहचान दिलवाई है।

11 दिसम्बर, 2022 को हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भाला। इसी के साथ प्रदेश में जनकल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन के नये युग का सूत्रपात हुआ। मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सचिवालय जाने की परम्परा को बदलते हुए सबसे पहले बालिका आश्रम टूटीकंडी गया। मैं बच्चों से मिला, बातचीत की। उन्होंने कोई मांग नहीं की लेकिन मैंने महसूस किया कि अभाव के बावजूद उनके चेहरों पर कुछ कर गुज़रने का जज़्बा था। नव वर्ष के तोहफे के तौर पर 101 करोड़ रुपये के शुरुआती प्रावधान के साथ सरकार ने मुख्यमंत्री सुख–आश्रय कोष की स्थापना की घोषणा की। सरकार ने निर्णय लिया कि अब ऐसे ही अनाथ बच्चों के माता भी हम होंगे और पिता भी। इनके सुख–दु:ख, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रमण की ज़िम्मेदारी भी अब हमारी ही है। प्रदेश के लगभग 6,000 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना के तहत 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' के रूप में अपनाने का हमने निर्णय लिया है।

हमारी सरकार सत्ता में सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। हमारी सरकार का पहला बजट सामान्य बजट नहीं है। मैंने लगातार विभिन्न विभागों की बैठकें कीं योजनाओं के बारे में जाना, समझा और चिन्तन–मनन किया। हम प्रदेश के हित में लीक से हट कर बजट लाए। आपको बजट में शामिल की गई योजनाओं का प्रभाव एक साल के भीतर ही दिखना शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने और हमारी आर्थिकी मज़बूत हो। हमारा पहला वायदा पुरानी पेंशन योजना बहाल करना था। हमने पहली कैबिनेट बैठक में ही 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में हमने 2. 31 लाख महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया।

विधवाओं एवं 40 से 69 प्रतिशतता वाले दिव्यांगजनों को पेंशन पाने के लिए हमने आय सीमा और ग्राम सभा से अनुमति की शर्त समाप्त कर दी है। विधवाओं और एकल नारियों को मकान बनाने के लिए मुख्यमन्त्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना आरम्भ की जा रही है। इसके तहत इस वर्ष 7000 ऐसी महिलाओं को 1. 50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है।

बेटियों को सम्पत्ति में समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित किया गया है। अब लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले असंवैधानिक खण्डों को हटाकर बेटियों को पैतृक सम्पत्ति के भू–स्वामित्व में समान अधिाकार सुनिश्चित किया गया है।

'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (पॉक्सो) के प्रावधानों के बारे में मुख्यमन्त्री सुरक्षित बचपन अभियान के अन्तर्गत प्रदेशवासियों, विशेषकर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। राज्य में नशे की समस्या से निपटने के लिए विशेष कार्य दल का गठन किया जा रहा है।

प्रदेश की आबो–हवा और बहता पानी हमारे लिए वरदान है। पहली बार हम एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मार्च, 2026 तक इस प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन एवं अमोनिया परियोजना के लिए समझौता किया है। इससे प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा तथा 3500 से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के माधयम से यातायात सुविधा प्रदान की जाएगी।

सरकार के प्रयासों से प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। निजी संचालकों को इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक ऑटो तथा ई–गुडस कैरियर्ज लेने पर 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये का उपदान दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में एशियन विकास बैंक की सहायता से 1311 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास योजना भी शुरू की जाएगी।

पर्यटन की दृष्टि से कांगड़ा में एयरपोर्ट का निर्माण विस्तार निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांगड़ा को प्रदेश की 'पर्यटन राजधानी' के रूप में विकसित किया जा रहा है। सभी ज़िला मुख्यालयों को वर्ष भर हवाई परिवहन से जोड़ने के लिए हेलीपोर्ट निर्माण और विकास के कार्य प्रगति पर हैं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश में रोपवे निर्माण को भी गति दी जा रही है।

राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है एक वर्ष के भीतर प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों के कुछ विभागों में रोबोटिक सर्जरी का कार्य शुरू हो जाएगा। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कैजुअल्टी विभाग को स्तरोन्नत कर 'एमरजेंसी मेडिसन विभाग' बनाने का भी निर्णय लिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा।

शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम वचनबद्ध है। हमारा मानना है कि नए स्कूल खोलने या अपग्रेड करने के स्थान पर वर्तमान में चल रहे विद्यालयों में अध्यापक, पुस्तकालय, लैब, अच्छे भवन व खेल मैदान जैसी गुणात्मक सुविधाएं दी जाएं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे–बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे, जो अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से लैस होंगे।

राज्य के युवाओं का कौशल विकास उन क्षेत्रों में किया जाएगा, जिन क्षेत्रों में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके दृष्टिगत विभिन्न सरकारी संस्थानों में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पैसों के अभाव में कोई भी मेधावी ग़रीब बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। राज्य में 200 करोड़ रुपये की राजीव गांधी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है जिसके अंतर्गत ग़रीब बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, एम.बी.ए., पी.एच.डी., बी. फार्मेसी, नर्सिंग आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय संस्थानों की सहायता से एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह मात्र एक प्रतिशत ब्याज, इन बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी सहयोग करेगा।

प्रदेश में निर्बाध जलापूर्ति उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रथम चरण में पायलट आधार पर नदी या डैम के साथ लगती कुछ नगर पंचायतों व नगर परिषदों में पेयजल योजनाओं को स्तरोन्नत किया जाएगा। अल्ट्रा–वॉयलेट किरणों का इस्तेमाल कर बैक्टीरिया–फ्री जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

गुणवत्तायुक्त सड़कें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमन्त्री सड़क एवं रख–रखाव योजना आरम्भ की जाएगी। इस वर्ष 1,060 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 1,505 किलोमीटर सड़कों की मैटलिंग व टारिंग तथा 70 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। 70 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों को डबल–लेन से फोर–लेन में स्तरोन्नत करने का कार्य भी किया जा रहा है।

कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों पर प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी निर्भर है लेकिन बढ़ती आबादी व प्रकृति पर निर्भरता के फलस्वरूप आज कृषि व पशुपालन कठिन व्यवसाय बनते जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हिम उन्नति योजना शुरू की जा रही है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप दूध, दालों, सब्जियों, फलों, फूलों, नगदी फसलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे।

राज्य सरकार कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी। दूध आधारित व्यवस्था को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिम गंगा योजना भी आरम्भ की जा रही है। इसके माध्यम से पशुपालकों को दूध का उचित दाम दिलवाया जाएगा और दूध के प्रसंस्करण व विपणन में सुधार लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तालाब निर्माण पर 80 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

जल विद्युत दोहन में निजी निवेश को बढ़ावा देने एवं रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिए आकर्षक नीति लाई जाएगी। विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपये की लागत का हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवेलपमेंट प्रोग्राम आरम्भ किया जाएगा। राज्य को आर्थिक रूप से मज़बूत करने के लिए बिजली बनाने के लिए उपयोग होने वाले पानी पर 'वाटर सैस' लगाने का निर्णय लिया गया है, इससे करोड़ों रुपये सालाना आय होने का अनुमान है।

युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए मुख्यमन्त्री रोज़गार संकल्प सेवा आरम्भ की जा रही है जिसके अंतर्गत दूर–दराज़ क्षेत्रों के युवाओं को भी राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमने इस वर्ष विभिन्न विभागों के 25 हज़ार क्रियाशील पदों को भरने का निर्णय लिया है। पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, आवास जैसे क्षेत्रों में लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये का निजी निवेश लाने के प्रयास किए जाएंगे जिससे लगभग 90 हज़ार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल खाली पहाड़ियों पर ही पौधरोपण किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के तहत 12 जिलों में खाली पहाड़ियों पर पौधरोपण किया जाएगा। पहले विकास कार्यों में वन स्वीकृतियाँ देने में बहुत समय लगता था। सरकार ने वन स्वीकृतियों में तेज़ी लाने के लिए ज़िला स्तरीय समितियां गठित की हैं, जो समय–समय पर अपने जिले से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ वन स्वीकृतियों के मामलों की समीक्षा करेंगी। इससे वन स्वीकृतियां जल्दी मिलेंगी और परियोजनाओं का कार्य तेज़ी से होगा।

प्रदेश में मौजूदा एकल खिड़की प्रणाली को ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन में परिवर्तित किया जाएगा। यह ब्यूरो निवेशकों को प्रदेश में 'आओ और काम शुरू करो' की सुविधा प्रदान करेगा तथा हिमाचल प्रदेश को आदर्श निवेश मित्र राज्य के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा।

युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्ट–अप आरम्भ करने के लिए राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना आरम्भ की जाएगी। योजना के तहत अनेक उद्यमों के साथ–साथ दंत–चिकित्सालयों में मशीनरी एवं औजार, मत्स्य इकाईयों, ई–टैक्सी तथा एक मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा।

मनरेगा दिहाड़ी प्रदेश में 212 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये की गई है। इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में मिलने वाली दिहाड़ी 266 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये की गई है। पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्क़र्ज़ के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

छोटे दुकानदारों व व्यापारियों को 50 हज़ार रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत उपदान देने के लिए मुख्यमन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना आरम्भ की जाएगी। व्यापारियों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के कर व शुल्क सम्बंधित लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सद्भावना योजना शुरु की जा रही है।

इस वर्ष प्रदेश सरकार ने नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 40 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का 'मिल्क सैस' दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया गया है।

अगर सही ढंग, सही नीति और सही सोच से आर्थिकी को मज़बूत करेंगे तो आने वाले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश, देश का सबसे विकसित और सम्पन्न राज्य होगा और इसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी।

सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार–मुक्त, संवेदनशील तथा जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य, सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों का समान व संतुलित विकास करना तथा ग़रीब व पिछड़े वर्गों का उत्थान है। प्रदेश को जन–कल्याण व विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने एवं प्रदेश की आर्थिकी मज़बूत बनाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

विकास की राह पर निरन्तर आपके सकारात्मक सहयोग की कामना रहेगी। आपने जनमत देकर हमें प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का मौक़ा दिया। हम आपके आभारी हैं।

हिमाचल दिवस की आप सभी को पुन: शुभकामनाएं।

हर्ष, संघर्ष...
प्रगतिशील हिमाचल 75 ऐतिहासिक वर्ष
1948 - 2023

सूचना-सम्पर्क-सेवा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल दिवस
के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को
हार्दिक शुभकामनायें

1.36 लाख की पुरानी पेंशन -
अब हुई बहाल

₹1500 मासिक पेंशन -
बढ़ा 2.31 लाख महिलाओं
का स्वाभिमान

1,40,000 नए रोज़गार -
होंगे युवा सामर्थ्यवान

सुख-आश्रय कोष (₹101 करोड़) -
सुनिश्चित हुई निराश्रितों की देखभाल

हिम गंगा योजना ₹500 करोड़ -
किसानों की बढ़ेगी आमदनी
मिलेंगे उचित दाम

मानदेय बढ़ोतरी से खुश -
पैरा वर्कर्ज़ और मनरेगा कामगार

हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेंगे
गुणात्मक शिक्षा के लिए
राजीव गांधी डे-बोर्डिंग संस्थान

सभी मेडिकल कॉलेजों में
रोबोटिक सर्जरी का होगा प्रावधान

ई–टैक्सी खरीद के लिए
50% की दर से उपदान

सभी जिला मुख्यालयों में होगा
हेलीपोर्ट का निर्माण

हरित ऊर्जा में हिमाचल
हो रहा प्रकाशमान

आलौकिक खूबसूरती और असाधारण वीरता की धरती देवभूमि हिमाचल प्रदेश के "प्रदेश गठन दिवस" पर सभी प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएँ।

इस शुभ अवसर पर आइये हम सब मिलकर एक नए दृढ़ इरादे के साथ समृद्ध हिमाचल प्रदेश का सृजन करने में भागीदार बनें।"

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

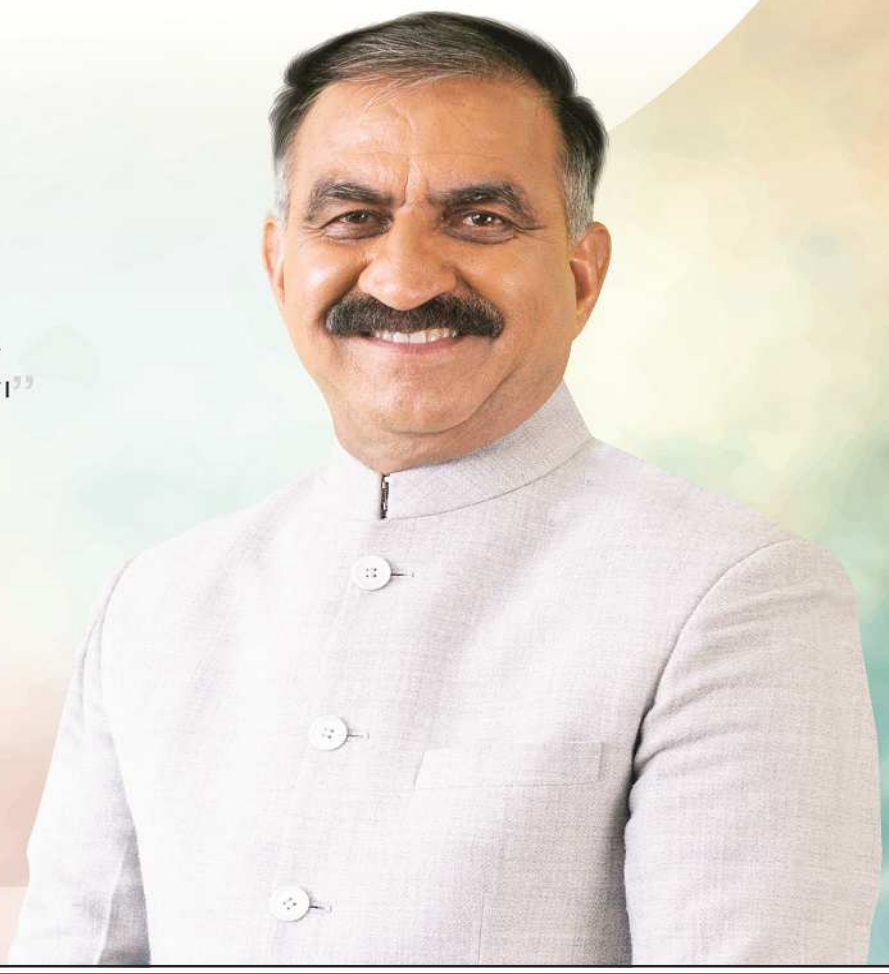

सुख की सरकार
हिमाचल सरकार

जारीकर्त्ता: सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
www.himachalpr.gov.in HimachalPradeshGovtIPRDept diprhimachal dprhp

PARTNERS

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

सुक्खू सरकार ने गारंटीयों की ओर बढ़ाया अगला कदम

- लाहौल–स्पीति में नौ हजार महिलाओं को जून से मिलेंगे 15 सौ रुपए प्रतिमाह
- संसाधन बढ़ाने के लिए केंद्रीय उर्जा सचिव से की भेंट
- प्रदेश की केन्द्रीय जल विद्युत परियोजनाओं में 40% हिस्सेदारी की रखी मांग

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने गारंटीयां पूरी करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुये हिमाचल दिवस के अवसर पर काजा में राज्य स्तरीय समारोह में लाहौल स्पीति की नौ हजार पात्र महिलाओं को जून माह से पंद्रह सौ प्रतिमाह देने की घोषणा की है। इससे पहले कर्मचारियों को ओल्ड पैन्शन इसी माह से बहाल कर दी है। नई पैन्शन योजना के तहत कर्मचारियों का जो अंशदान काटा जा रहा था वह इसी के साथ बन्द हो जायेगा और यह हर कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से एक सीधा लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। अन्य गारंटीयां भी अपने इसी कार्यकाल में यह सरकार पूरी कर देगी यह भरोसा प्रदेश की जनता को होने लगा है। यह गारंटीयां और विकास के अन्य कार्य पूरे करने के लिये संसाधन कैसे बढ़ाये जायें इस दिशा में भी सकारात्मक व्यवहारिक कदम उठाने शुरू कर दिये गये हैं। इस कड़ी में काजा में ही केन्द्रीय ऊर्जा सचिव से भेंट करके प्रदेश में केंद्रीय एजैन्सियों द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40% करने का विषय उठाया है। केंद्रीय स्वामित्व वाली जो परियोजनाएं अपनी लागत वसूल कर चुकी हैं उनमें यदि प्रदेश की हिस्सेदारी कुछ भी बढ़ पाती है तो वह राज्य को सीधा लाभ होगा। केन्द्रीय योजनाओं में हिस्सा बढ़ाने के साथ ही शानन जल विद्युत परियोजना की 100 वर्ष की लीज अवधि अगले वर्ष समाप्त होने पर उसका स्वामित्व भी प्रदेश को सौंपने का मुद्दा भी केन्द्रीय उर्जा सचिव से उठाया गया है। इस परिदृश्य में जिस तरह की वित्तीय स्थिति इस सरकार को विरासत में मिली है उसे सामने रखते हुए इस सरकार को जहां संसाधन बढ़ाने के लिये काम करना होगा वहीं पर कर्ज भार बढ़ाने से भी बचाना होगा। सुक्खू सरकार को 31 मार्च तक ही करीब 5000 करोड़ का कर्ज उठाना पड़ गया है। अब अगले वित्तीय वर्ष के लिये 12000 करोड़ का कर्ज उठाने का प्रयास किया जा रहा है। 12000 करोड़ के कर्ज का आंकड़ा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता में सामने रखा है। इस प्रस्तावित कर्ज के आंकड़े पर सरकार या कांग्रेस के किसी बड़े पदाधिकारी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। प्रतिक्रिया न आना इस आंकड़े की पुष्टि करता है। यह आंकड़ा उस समय बहुत बड़ा हो जाता है जब जयराम सरकार द्वारा पांच वर्षों में 23800 करोड़ का कर्ज लेने का आंकड़ा बजट सत्र में सदन के पटल पर आ चुका है। सरकार बनने के बाद जिस तरह से कुछ चीजों के दाम/दरें बढ़ायी गयी उनको लेकर जनता में चर्चा चल पड़ी है। यदि यह सरकार कर्ज लेकर और वस्तुओं तथा सेवाओं के दाम बढ़ाकर ही गारंटिया पूरी करने की बात करती है तो यह सरकार और प्रदेश के व्यापक हित में नहीं होगा। क्योंकि इससे महंगाई और बेरोजगारी ही बढ़ेगी जिससे जनता पहले ही परेशान है। संसाधन बढ़ाने के उपाय करने के साथ ही सरकार को अवांछित खर्चों पर लगाम लगानी होगी। इसी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवहारिक स्तर पर कार्यवाही करनी होगी। जयराम सरकार के खिलाफ भी यह बड़ा आरोप रहा है कि उसने किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। अब यह सरकार भी अपने आरोप पत्र अब तक विजिलैन्स को नहीं भेज पायी है। जबकि इसे तो जारी भी चुनाव के दौरान किया गया था।

"देश के गद्दारों को गोली मारो" प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी

शिमला/शैल। स्मरणीय है कि जनवरी 2020 में यह भाषण एक रैली को संबोधित करते हुये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने यह भाषण दिया था। उस दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में केन्द्र सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन चल रहे थे। ऐसा ही एक धरना शाहीन बाग में चल रहा था। वहीं पर एक भाजपा चुनावी रैली को संबोधित करते हुये इन नेताओं ने यह भाषण दिये थे। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुये इनके चुनाव प्रचार में कुछ समय के लिये प्रतिबन्ध भी लगा दिया था। इन भाषाओं का संज्ञान लेते हुए सी.पी.एम. नेता वृंदा करात ने दिल्ली की एक अदालत में इनके खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने की मांग कर दी। अदालत ने यह मांग यह कह कर अस्वीकार कर दी की एफ.आई.आर. दर्ज के लिये अनुमति चाहिये जो इस मामले में नहीं है। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ करात दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गयी। लेकिन उच्च न्यायालय ने भी एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिये स्वीकृति चाहिये के तर्क को बहाल रखते हुये वृंदा की याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ वृंदा एस.एल.पी. में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस के.एम.जोसेफ और बी. वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने इस पर नोटिस जारी कर दिये हैं। उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मैजिस्ट्रेट के अनुमति के तर्क को सही नहीं माना है। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ही एफ. आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दे रखे हैं। एफ. आई.आर. दर्ज करने के लिये भ्रष्टाचार के मामलों में अनुमति चाहिये अपराधिक मामलों में नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि के मामले में आये फैसले के बाद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा प्रकरण की गंभीरता बढ़ जाती है। राहुल गांधी के ब्यान से इन नेताओं का ब्यान ज्यादा गंभीर है। राहुल ने भी चुनावी रैली में ही ब्यान दिया था और उसका कोई संज्ञान चुनाव आयोग ने नहीं लिया था। जबकि अनुराग और प्रवेश शर्मा के ब्यानों का संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने इन के प्रचार पर भी कुछ घंटों के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया था। फिर इनके ब्यानों के कुछ दिन बाद शाहीन बाग में बंदूक की घटना घट गयी थी। आज जिस तरह का राजनीतिक माहौल बनता जा रहा है उसके परिदृश्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के बाद इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। अनुराग ठाकुर हिमाचल से सांसद हैं ऐसे में प्रदेश की राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

– बिकाऊ है – – बिकाऊ है – – बिकाऊ है –

8 बिघा 6 बिस्वा में फैला
सेब बगीचा
नैशनल हाईवे से एक किलोमीटर दूर
जैस घाटी ठियोग में
500 पौधे लगे हुये

संपर्क करें: – 98162 – 07501, 98820 – 3 0717